



आदरणीय प्रधान मंत्री जी

देश का अन्न दाता किसान आज़ादी के ७० वर्षों बाद भी स्वतंत्र नहीं हुआ है | उसके कृषि कार्य की सभी गतिविधियों पर किसी न किसी का नियंत्रण है | किसानों की मुख्या समस्या घटती हुए जोत (किसी क्षेत्रफल) है और छोटे छोटे खेतों पर उसके परिवार की निर्भरता |

दुर्भाग्य से राजनितिक दल अपने वोटों की लिए किसानों का कर्ज़ माफ़ कर देते हैं | सन 2008 में कांग्रेस सरकार द्वारा 60,000 करोड़ का कर्ज़, फिर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऋण माफ़, 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा द्वारा किया गया वादा जिसमें 36000 करोड़ का ऋण माफ़ किया गया | उत्तर प्रदेश की लगी हुए ऋण माफ़ी की आग अब समस्त भारत को अपने लपटों में लेने को तैयार है | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक जीता जागता नमूना है | एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के चुनाव जितने के लिए की गयी कृषि ऋण माफ़ी योजना की सम्पूर्ण राष्ट्र को लगभग 5 लाख करोड़ कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी की एक साल की राजस्व का लगभग आधा | यह सुनिश्चित है कि हर राजनितिक दल चुनाव जितने के लिए कृषि ऋण माफ़ी को एक वोट पाने के हथियार के रूप में जरूर उपयोग में लाएंगे | यह दुखद है की कारोबारी वर्ग को इस राजनितिक निर्णयों की कीमत चुकाने पड़ती है |

इंडियन बिजनेस पार्टी, किसानों को एक कारोबारी मानती है और कृषि क्षेत्र की सुधर हेतु कुछ प्रस्ताव रखती है

1. देश की एक तिहाई किसान किराय की खेत पर कृषि कार्य करते हैं | भारत में कृषि भूमि को किराए पर देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है | जमींदार लोग अवैध रूप से छोटे छोटे किसानों को अपनी भूमि बटाई पर दे देते हैं, जिसकी सरकारी रिकॉर्ड में कोई लिखा पड़ी नहीं | किरायदार किसान कि विडम्बना यह है कि उसे न तो बैंक ऋण ही मिल पता है और न ही फसल के नुकसान होने पर मुआवज़ा | बेचारा किरायदार किसान पुरे साल सूद खोरो से ऋण ले ले कर खेती करता है और साल की आखिर में उसे सिर्फ शून्य मिलता है | सरकार को तुरंत एक कानून बना कर कृषि खेतों की किराएदारी को वैधानिक रूप देना चाहिय तथा किराय की खेती पर बैंक द्वारा ऋण मिलना चाहिय |

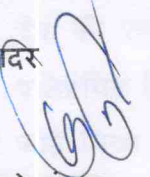
2. कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट खेती पर कानून ला कर इस प्रकार की खेती को वैधानिक बनाना चाहिय |

3. सरकार किसानों की न्यूनतम आय को सुनिश्चित करे और फसलों की कीमत का 85 % भाग किसानों को मिले और शेष 15 % बिचौलियों को | अभी यह अनुपात उल्टा है |

4. किसानों को कृषि पर निर्भरता कम करके स्वरोजगार अपनाने की लिए प्रोत्साहित करना चाहिये ।
5. ऐसा कानून बनाना चाहिये की कृषि ऋण माफ़ी योजना चुनावी घोषणा पत्र का विषय न बने ।
6. छोटे छोटे खेतों पर सहकारी (co-operative) पद्धति को पुनः जीवित किया जाय ।

सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि अन्न प्रदाता किसानों को कोई विकल्प नहीं है । यदि देश का किसान अशांत है तो देश की सीमा भी सुरक्षित नहीं हो सकती क्योंकि अधिकांश सैनिक कृषक परिवार से आते हैं ।

आशा है कि भारत सरकार आपके नेतृत्व में किसानों की समस्याओं का स्थाई समाधान खोजने में सफल रहेगी और देश अन्न के अन्न की भंडार सदैव भरे रहेंगे ।

सादर


वी के बसल
राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिनांक 14 जून 2017

सेवा में
माननीय प्रधान मंत्री जी
भारत सरकार
नई दिल्ली